



**NEERAJ®**

# M.C.O.-15

## भारत का विदेश व्यापार और निवेश

( India's Foreign Trade and Investment )

Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers

Based on

# IGNOU.

& Various Central, State & Other Open Universities

*By: Sajnay Jain & Ved Prakash Sharma*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com)

Website: [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 400/-**

## Content

# भारत का विदेश व्यापार और निवेश ( India's Foreign Trade and Investment )

Question Paper—June-2024 (Solved).....	1-3
Question Paper—December-2023 (Solved).....	1
Question Paper—June-2023 (Solved).....	1

---

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
<b>विदेश व्यापार और निवेश ( Foreign Trade and Investment )</b>		
1.	विदेश व्यापार का अवलोकन ..... ( Overview of Foreign Trade )	1
2.	विदेशी निवेश ( Foreign Investment ) .....	15
3.	भारत का भुगतान संतुलन ..... ( India's Balance of Payments )	37
<b>विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन ( Foreign Trade and Export Promotion )</b>		
4.	भारत का विदेश व्यापार ( India's Foreign Trade ) .....	49
5.	विश्व व्यापार और भारत ( World Trade and India ) .....	68
6.	भारत में निर्यात संवर्धन के उपाय ..... ( Export Promotion Measures in India )	89

**प्रमुख उत्पादों की व्यापार संभावनाएँ  
(Trade Prospects of Major Products)**

7. कृषि उत्पाद ( Agricultural Products ) .....	107
8. कपड़ा एवं वस्त्र ( Textiles and Garments ) .....	124
9. रत्न व आभूषण तथा हस्तशिल्प .....	141
( Gems and Jewellery and Handicrafts )	
10. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ( Electronic Commodities ) .....	154
11. इंजीनियरिंग वस्तुएं ( Engineering Goods ) .....	169
12. सेवाओं में व्यापार ( Trade in Services ) .....	184

**चयनित बाजारों की व्यापार संभावनाएँ  
(Trade Prospects of Select Markets)**

13. संयुक्त राज्य अमेरिका ( United States of America ) .....	204
14. यूरोपियन यूनियन ( European Union ) .....	217
15. जापान ( Japan ) .....	235
16. सार्क और दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ ( SAARC and ASEAN ) .....	248
17. पश्चिम एशिया ( West Asia ) .....	263



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

भारत का विदेश व्यापार एवं निवेश  
( India's Foreign Trade and Investment )

M.C.O.-15

समय : 3 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. “नई विदेशी निवेश नीति को भारत में विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए एक वरदान के रूप में वर्णित किया गया है।” क्या आप इस कथन को उचित ठहराते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-30, प्रश्न 4

प्रश्न 2. भारत के निर्यात की दिशाओं और इन प्रवृत्तियों के कारणों का परीक्षण करें। निर्यात संवर्धन परिषदों की भूमिका स्पष्ट करें।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-52, 'भारत के विदेश व्यापार की दिशा' तथा अध्याय-6, पृष्ठ-90, 'निर्यात संवर्धन में शामिल संगठन'

प्रश्न 3. भारतीय संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्त्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-32, प्रश्न 6, प्रश्न 7, पृष्ठ-34, प्रश्न 8

प्रश्न 4. सुधार के लिए भारत के विदेशी व्यापार के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का परीक्षण करें।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-65, प्रश्न 10

प्रश्न 5. कृषि उत्पादों और उसके निर्यात पर डब्ल्यूटीओ समझौतों के प्रभाव की जाँच करें।

उत्तर-विश्व व्यापार संगठन (WTO) व्यवस्था का कृषि उत्पादों और निर्यात सहित वैश्विक कृषि व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत और अन्य विकासशील देशों जैसे देशों के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है। WTO के कृषि समझौते (AoA) ने कृषि नीति, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और घरेलू कृषि बाजारों को प्रभावित किया है। नीचे कृषि उत्पादों और निर्यात पर WTO व्यवस्था के प्रभाव की एक जांच है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में:

WTO के कृषि ढाँचे की मुख्य विशेषताएं

1. कृषि समझौता (AoA)-AoA WTO की कृषि नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कृषि व्यापार को और अधिक बाजार-उन्मुख बनाना है। समझौते के तीन मुख्य घटक हैं-

● बाजार पहुँच-कृषि बाजारों तक अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष पहुँच बनाने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी।

● घरेलू समर्थन-घरेलू सब्सिडी के स्तर पर प्रतिबंध जो कृषि उत्पादन और व्यापार को विकृत करते हैं।

● निर्यात सब्सिडी-कुछ देशों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने वाली निर्यात सब्सिडी में क्रमिक कमी या उन्मूलन।

2. स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (एसपीएस)-एसपीएस समझौता खाद्य सुरक्षा और पशु/पौधे स्वास्थ्य मानकों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। हालांकि यह देशों को अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए और व्यापार में छिपी बाधाओं के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कृषि और निर्यात पर विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव

1. बेहतर बाजार पहुँच-

कम टैरिफ-विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था ने व्यापार के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम कर दिया है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों के कृषि निर्यातकों के लिए बाजार पहुँच में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, चावल, मसाले और चाय जैसे भारतीय कृषि उत्पादों को उदार व्यापार के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजारों तक व्यापक पहुँच मिली है।

निर्यात बाजारों का विविधीकरण-अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के खुलने से भारत जैसे देश अपने कृषि निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने में सक्षम हुए हैं। इससे कुछ व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता

कम हो जाती है और यूरोप, अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के उच्च-मांग वाले बाजारों में प्रवेश करने के अधिक अवसर मिलते हैं।

## 2. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

**वैश्विक मानक और गुणवत्ता सुधार**—WTO व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को लागू करके कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय निर्यातकों ने खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण में बेहतर प्रथाओं को अपनाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।

**व्यापार उदारीकरण**—कृषि व्यापार के उदारीकरण ने विकासशील देशों को अपने तुलनात्मक लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। भारत के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले चावल, मसाले, चाय, फलों और सब्जियों के विशाल उत्पादन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

**3. कृषि निर्यात में वृद्धि**—भारत जैसे देशों में, WTO व्यवस्था के तहत कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, समुद्री भोजन और मसालों जैसे कृषि उत्पादों के भारत के निर्यात में मात्रा और मूल्य में वृद्धि हुई है।

**नए बाजारों का उदय**—WTO वार्ताओं ने विकासशील देशों के लिए नए निर्यात बाजार खोलने में मदद की है। उदाहरण के लिए, भारतीय उत्पादों को अब अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि लैटिन अमेरिका में भी बाजार मिल रहे हैं, जहां उन्हें कम टैरिफ और व्यापार सुविधा उपायों का लाभ मिल रहा है।

**4. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा**—निर्यात सब्सिडी को कम करने या खत्म करने के WTO के प्रयासों ने, विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा, एक अधिक समान खेल का मैदान तैयार किया है। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां किसान निर्यात बाजारों में सफल होने के लिए सब्सिडी के बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर भरोसा करते हैं।

**व्यापार विकृतियों में कमी**—WTO के माध्यम से, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन (सब्सिडी) की अधिक जांच और कमी होती है, जिससे अक्सर विकासशील देशों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।

**5. सुधारों और नीति समायोजनों को प्रोत्साहन**—AoA ने भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी घरेलू कृषि नीतियों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है, विशेष रूप से सब्सिडी युक्तिकरण और बाजार-उन्मुख सुधारों की शुरुआत जैसे क्षेत्रों में। यद्यपि ये सुधार धीमे रहे हैं और इन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, फिर भी इनसे कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में मदद मिली है।

**कृषि और निर्यात पर WTO शासन के नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ**

**1. विकसित बाजारों में संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ**—सीमित बाजार पहुँच—व्यापार को उदार बनाने के AoA के लक्ष्यों के बावजूद, कई विकसित देश अभी भी उच्च टैरिफ लगाते हैं और डेयरी, चीनी और मांस जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों पर टैरिफ-दर कोटा का उपयोग करते हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों की इन बाजारों में अपने कृषि निर्यात का विस्तार करने की क्षमता को सीमित करता है।

**गैर-टैरिफ बाधाएँ**—जबकि टैरिफ कम हो गए हैं, गैर-टैरिफ बाधाएँ (NTB), जिसमें सख्त SPS उपाय शामिल हैं, महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में उभरी हैं। विकसित देश अक्सर सख्त गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को लागू करते हैं जिन्हें विकासशील देशों को पूरा करना मुश्किल लगता है, जो प्रवेश के लिए छिपी हुई बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।

## 2. घरेलू कृषि नीतियों पर प्रभाव

**घरेलू समर्थन पर बाधाएँ**—घरेलू सब्सिडी पर WTO के प्रतिबंध (जिन्हें एम्बर, ब्लू, और ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है) विकासशील देशों की अपने कृषि क्षेत्रों का समर्थन करने की क्षमता को सीमित करते हैं। भारत के लिए, जहाँ खेती मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर होती है और किसान उर्वरकों और बिजली जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, यह बाधा महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।

**खाद्य सुरक्षा चिंताएँ**—कई विकासशील देशों का तर्क है कि WTO की कृषि नीतियाँ खाद्य सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली (PDS) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, WTO नियमों के तहत जांच के दायरे में आ सकती हैं क्योंकि उन्हें व्यापार-विकृत करने वाला माना जाता है।

**3. विकसित देशों में सब्सिडी-असमान खेल का मैदान**—सब्सिडी कम करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद, विकसित देश, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका, अपने कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त घरेलू समर्थन प्रदान करना जारी रखते हैं। ये सब्सिडी उनके किसानों को विकासशील देशों के किसानों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है, जिससे विकासशील देशों के लिए वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है।

**विकृत कीमतें**—विकसित देशों के सब्सिडी वाले उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे कीमतें नीचे गिर सकती हैं और विकासशील देशों में कृषि उत्पादकों की निर्यात क्षमता को नुकसान पहुँच सकता है।

# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत का विदेश व्यापार और निवेश ( India's Foreign Trade and Investment )

## विदेश व्यापार और निवेश ( Foreign Trade and Investment )

### विदेश व्यापार का अवलोकन ( Overview of Foreign Trade )



#### परिचय

ऐतिहासिक काल से ही राष्ट्रीय सीमा पार से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के आदान-प्रदान का प्रचलन रहा है। इसके विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत जैसे विकासशील देश में, व्यापार नीति आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। भारत की व्यापार नीति के दोहरे उद्देश्य हैं—निर्यात को बढ़ावा देना और आवंटित विदेशी मुद्रा से आयात के स्तर को सीमित करना। भारत जैसे देश की मूल समस्या उद्योग विनिर्माण के लिए जरूरी सामग्री, जैसे—औद्योगिक कच्चे माल, पूंजी, वस्तुओं और प्रौद्योगिकी की कमी होती है, जिसे केवल आयात द्वारा ही दूर किया जा सकता है, इसलिए व्यापार नीति का मूल उद्देश्य निर्यात संवर्धन और आयात प्रबंधन के विभिन्न उपायों के अनुरूप ही रहता है, जिनमें एक भारत के सेवा क्षेत्र, लघु उद्योग और रोजगार उत्पादन को बढ़ावा देना भी है।

#### अध्याय का विहंगावलोकन

##### विदेशी व्यापार के लिए कानूनी प्रारूप का अवलोकन

भारत का विदेशी व्यापार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (Development - Regulation Act, 1992) के अंतर्गत नियंत्रित होता है, जबकि विदेशी मुद्रा के रूप में निर्यात और आयात व्यापार लेन-देन के नियम विदेश विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) के तहत नियंत्रित होते हैं। परिवहन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से माल और सेवाओं दोनों के निर्यात और आयात संबंधी लेन-देन का भौतिक संचालन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयोजित और विनियमित किया जाता है। वस्तुओं की

गुणवत्ता पर निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाले चार प्रमुख अधिनियम इस प्रकार हैं—

##### विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992

इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में आयात की सुविधा और निर्यात संवर्धन उपायों के द्वारा विदेशी व्यापार और विनियमन के विकास को सुगम बनाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत आयातक-निर्यातक कोड संख्या (IEC) के निर्धारण द्वारा निर्यात और आयात की अनुमति भी प्रदान की जाती है। यह अधिनियम आयात-निर्यात नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन सहित अधिनियम के प्रयोजन हेतु विदेशी कारोबार के महानिदेशक की नियुक्ति के लिए और देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचने पर भी आयातक-निर्यातक कोड संख्या (IEC) को निरस्त करने तथा दंड देने के लिए भी अधिकृत है।

##### विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभिक दौर में, भारत में होने वाले विनियम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1939 में कुछ नियम लागू किए गए थे। बाद में यह अधिनियम विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 द्वारा बदल दिया गया था। यह अधिनियम 1973 में फिर संशोधित किया गया और इसे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (FERA) के नाम से जाना गया। 1993 में इसका पुनः संशोधन किया गया, लेकिन FERA उदारीकरण के बाद की नीतियों का सामना करने में विफल रहा। अंत में, वर्तमान खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए FERA के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को 1999 में लागू किया गया था। FEMA सरकार का एक अधिनियम है, जिसने भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून को



समेकित और संशोधित किया है। FEMA अधिनियम का उद्देश्य बाहरी भुगतान, व्यवस्थित विकास और भारत में विदेशी विनिमय के लिए बाजारों के रखरखाव को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम के अनुसार, विदेशी प्रतिभूतियों या विनिमय से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन FEMA के अनुमोदन के बिना नहीं किए जा सकते। सभी लेन-देन 'अधिकृत व्यक्तियों' के माध्यम से किए जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक FEMA के प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार नियम बनाता है, जिन्हें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाता है।

### सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

तीन अधिनियमों (समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, भूमि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विमान शुल्क अधिनियम, 1934) के स्थान पर 13 दिसंबर 1962 को समेकित अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुसार निर्यात और आयात लेनदेनों का विनियमन करना, राजस्व एकत्र करना तथा गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

### निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम को 1963 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य निर्यात व्यापार को गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से मजबूत बनाना था। निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और उससे जुड़े हुए मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सही विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 1964 को निर्यात निरीक्षण परिषद (Export Inspection Council, EIC) की स्थापना की गई थी। EIC की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत अधिसूचित उत्पाद और अपनी गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब होता है जब ग्राहकों को विदेशी बाजारों से कम मूल्य में उत्पाद प्राप्त होता है और विक्रेताओं को घरेलू बाजार की अपेक्षा उनके उत्पादों पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं—

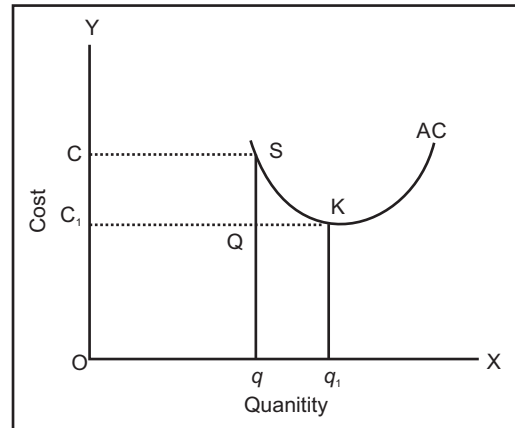
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, कोई भी देश वे वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकता है, जिनको वह उत्पादित करने में सक्षम नहीं है अथवा उनको उत्पादित करने में उसको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- कुछ घरेलू उद्योग कच्चे माल, आवश्यक घटकों और उपकरणों की आपूर्ति के लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने में सहायता करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, एक देश निश्चित उत्पादों के उत्पादन में अपनी विशिष्टता की पहचान कर उन उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात कर सकता है। इस प्रकार के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके, ये देश उन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता बढ़ा सकता है, जिससे श्रम विभाजन और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने के अवसर प्रदान करता है। अतः निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच बहुत अधिक स्तर की प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिसके कारण उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरकारी राजस्व बढ़ाने, वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाने, रोजगार प्रदान करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न देशों के मध्य सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है।

### विदेश व्यापार और आर्थिक विकास

विदेशी व्यापार को विकास का इंजन कहा जाता है, क्योंकि इससे देश में बेकार पड़े संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास होता है, कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि करने और बेरोजगारी कम करने में सहायक है। आयात और निर्यात बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न करके यह विकासशील परिवर्तन को गति प्रदान करता है। निर्यात क्षमता का अधिकतम उपयोग, वैश्विक मापदंडों के अनुसार व्यापार का विस्तार, नई तकनीकों का विकास आदि विदेशी व्यापार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिससे देश का विकास होता है। बड़े पैमाने पर निर्यात करने से महंगाई दर बढ़ती है, जिससे श्रमिकों का वेतनमान बढ़ता है। विदेशी व्यापार व्यापारिक औद्योगीकरण द्वारा तकनीकी स्थानांतरण को बढ़ाता है, जो मानवश्रम की कुशलता में वृद्धि करते हैं। बिना किसी मूल्य वृद्धि के घरेलू व्यवसाय की लाभकारिता बढ़ती है, जो प्रदत्त चित्र से स्पष्ट है—



AC औसत लागत वक्र है। उत्पादन की मात्रा  $Oq_1$  होने पर प्रति इकाई उत्पादन की औसत लागत सबसे कम होगी। हालांकि, घरेलू पाबंदी के कारण उत्पादन स्तर  $Oq$  और संबंधित औसत लागत  $OC$  होती है।  $qq_1$  मात्रा निर्यात करने पर कोई भी कंपनी अपनी उच्चतम क्षमता का उपयोग करके औसत लागत को  $CC_1$  तक कम कर सकती है। इस 'न लाभ न हानि' की स्थिति में भी निर्यात करना उचित होता है, क्योंकि घरेलू क्षमता में वृद्धि से कंपनी की लाभकारिता बढ़ती है। इस प्रकार मूल्य में वृद्धि के बिना भी निर्यात लाभ को बढ़ाता है।

**व्यापार का स्तर और व्यापार संतुलन**—किसी राष्ट्र के व्यापार का स्तर इसकी अर्थव्यवस्था का आकार, इसकी भौगोलिक स्थिति और इसके व्यापार की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। व्यापार की स्थिति का अनुमान उसके निर्यात से होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद के निर्यात प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। जहां निर्यात और आयात के बीच एक करीबी संतुलन होता है, वहां भी अर्थव्यवस्था के लिए उच्च स्तर के व्यापक व्यापार के परिणामों से चिंता की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि देश कुछ मुख्य निर्यात क्षेत्रों पर अधिक निर्भर होता है, तो उन उत्पादों की माँग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बड़े व्यापार घाटे विदेशी कर्ज को बढ़ा सकते हैं, जिससे देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि वे व्यापार संतुलन को बनाए रखें।

### व्यापार नीति और रणनीति

व्यापार नीति उन सभी नीतियों को संदर्भित करती है, जो किसी देश के व्यापार व्यवहार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जो उसकी विकास रणनीति पर निर्भर करता है। व्यापार नीति की बाह्य-उन्मुखी रणनीति उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त व्यापार पर बल देती है। इसमें पूंजी, श्रम, माल का मुक्त आवागमन, बहुराष्ट्रीय उद्यमों की स्थापना और मुक्त संचार व्यवस्था जैसी गतिविधियां सम्मिलित हैं। जबकि अन्तः-उन्मुखी रणनीति विदेशी सहायता, उत्पादक घटकों की गतिविधियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संचार को निषेध करती है। हालांकि, अधिकांश देश अन्तः-उन्मुखी रणनीति को नहीं अपनाते।

**बाह्य-उन्मुखी रणनीति के लिए तर्क**—बाह्य-उन्मुखी रणनीति के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश से शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे नए विचारों और तकनीकों का उदय होता है और जीवन स्तर सुधरता है।

**अन्तः-उन्मुखी रणनीति के लिए तर्क**—अन्तः-उन्मुखी रणनीति के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अंतर्निर्देशी नीतियां घरेलू तकनीकों के विकास पर बल देती हैं, जिससे स्वदेशी

प्रतिभाओं की शक्ति को बल मिलता है तथा यह बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाती हैं।

### भारत के विदेश व्यापार के प्रमुख पहलू

वर्ष 2020 में, विश्व में वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 1.6% और आयात 2.1% रहा, जबकि वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 4% और आयात में 3.2% रही। वर्ष 2021 में, विश्व में वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 1.8% और आयात 2.5% रहा, जबकि वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 4% और आयात में 3.5 % रही। 2020 में, माल निर्यात में भारत 21वें स्थान पर रहा और 2021 में 18वें स्थान पर रहा। जबकि 2020 में व्यापारिक आयात में भारत ने 14वां स्थान और 2021 में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सेवाओं के निर्यात में भारत वर्ष 2020 में 7वें तथा सेवाओं के आयात में 10वें स्थान पर रहा। जबकि 2021 में सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान 8वां और सेवाओं के आयात में 10वां ही रहा।

### भारत के विदेश व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति

भारतीय विदेश व्यापार के सन्दर्भ में वर्ष 1983-2021 में निर्यातों में बढ़त देखी जा सकती है। 1991-92 से निर्यात बढ़कर 2021-22 में 422004.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। आयात भी 1994-95 से बढ़कर 2021-22 में 613052.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापार शेष भी बढ़कर 2021-22 में 613052.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

#### निर्यात

निम्न तालिका 2020-21 के शीर्ष 10 वस्तुओं के निर्यात को दिखाती है। तालिका से स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग वस्तुओं (26.29%) का निर्यात शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि प्लास्टिक और लिनोलियम (2.56%) का निर्यात सबसे कम रहा।

#### 2020-21 के शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात

Rank	Commodity	2020-21	Share% in 2020-21
1	Engineering goods	76.72	26.29
2	Gems and jewellery	26.02	8.92
3	Petroleum products	25.80	8.84
4	Drugs and pharmaceuticals	24.44	8.38
5	Organic and inorganic chemicals	22.09	7.57
6	RMG of all textiles	12.27	4.21
7	Electronic goods	11.09	3.80
8	Cotton yarn/fabs./made-ups, handloom products etc.	9.83	3.37
9	Rice	8.83	3.03
10	Plastic and linoleum	7.46	2.56

4 / NEERAJ : भारत का विदेश व्यापार और निवेश

**आयात**

निम्न तालिका में 2020-21 के शीर्ष 10 वस्तुओं के आयात को दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार, पेट्रोलियम और पेट्रो उत्पाद (20.96%) शीर्ष स्थान पर थे। अतः सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम और उसके उत्पादों का किया गया। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्यात से प्राप्त आय से ही आयात की लागत का भुगतान किया जाना चाहिए।

**2020-21 के शीर्ष 10 वस्तुओं का आयात**

Rank	Commodity	2020-21	Share% in 2020-21
1	Petroleum, crude and products	82.68	20.96
2	Electronic goods	54.29	13.76
3	Gold	34.60	8.77
4	Machinery, electrical and non-electrical	30.08	7.63
5	Organic and inorganic chemicals	19.83	5.03
6	Pearls, precious and semi-precious stones	18.89	4.79
7	Transport equipment	18.65	4.73
8	Coal, coke and briquettes, etc.	16.27	4.13
9	Artificial resins, plastic materials, etc.	13.51	3.43
10	Iron and steel	12.04	3.05

**निर्यात की दिशा**

तालिका के अनुसार, 2020-21 में भारत के मुख्य निर्यात का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके पश्चात् चीन, हांगकांग, बांग्लादेश आदि आते हैं। तालिका के अनुसार, हमारे निर्यात गंतव्य का एक तिहाई से अधिक भाग केवल चार देशों में केंद्रित है। इसलिए, अन्य देशों में भी निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।

**2020-21 में भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों की सूची**

S.No.	Country	2020-21	Share% in 2020-21
1	U S A	51.63	17.69
2	China	21.19	7.26
3	U A E	16.68	5.72
4	Hong Kong	10.16	3.48
5	Bangladesh	9.69	3.32
6	Singapore	8.68	2.97
7	U K	8.21	2.81
8	Germany	8.13	2.78
9	Nepal	6.84	2.34
10	Netherland	6.47	2.22

**आयात की दिशा**

**2020-21 में भारत के शीर्ष 10 आयात गंतव्यों की सूची**

S.No.	Country	2020-21	Share% in 2020-21
1	China	65.21	16.53
2	USA	28.89	7.32
3	UAE	26.62	6.75
4	Switzerland	18.23	4.62
5	Saudi Arab	16.19	4.1
6	Hong Kong	15.17	3.85
7	Iraq	14.29	3.62
8	Germany	13.64	3.46
9	Singapore	13.30	3.37
10	Korea Rp	12.77	3.24

तालिका के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारत के शीर्ष 10 आयात गंतव्यों में चीन (16.53%) पहले स्थान पर था, जिसके पश्चात् अमेरिका (7.32%), संयुक्त अरब अमीरात (6.75%), स्विट्जरलैंड (4.62%), सऊदी अरब (4.1%) आदि आते हैं।

**सेवाओं का निर्यात**

सेवा उद्योग का निर्यात ने भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सेवाओं में दूरसंचार, परिवहन, पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, कंप्यूटर संबंधित सेवाएं आदि सम्मिलित हैं।

**सेवाओं में वैश्विक व्यापार**—सेवा निर्यात में विश्व व्यापार में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि देखी गयी है, जो माँग और आपूर्ति दोनों से प्रभावित होती है। कंप्यूटर और दूरसंचार के जेनेरिक तकनीक में प्रगति के साथ सेवा निर्यात में माँग बढ़ी है, क्योंकि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में नई तकनीकों और नवाचारों ने सेवा क्षेत्र में विस्तार पर बल दिया है। नए बाजारों के खुलने, उपभोक्ताओं की आवश्यकता और वैश्वीकरण रणनीतियां आदि ने सेवाओं की माँग को बढ़ाया है। वहीं कई सेवाएँ जो पहले व्यावसायिक फर्मों की घरेलू गतिविधियाँ थीं, विशिष्ट होने के कारण बाहरी व्यावसायिक फर्मों को भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, मुक्त बाजार का अपेक्षित विस्तार, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के कारण नई सहस्राब्दी में सेवा व्यापार में वृद्धि की संभावना है।

**भारत की सेवाओं का निर्यात**

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) में सेवाएँ प्रदान करने के चार तरीके बताए गए हैं। पहला, सीमा पार आपूर्ति को दर्शाता है, जैसे—कॉल सेंटर। दूसरा, उपभोक्ताओं की गतिशीलता से सम्बंधित है, जैसे—चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और पर्यटन के लिए लोग विदेश से आते हैं। तीसरा, वाणिज्यिक उपस्थिति को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ। चौथा, मूलतः व्यक्तियों की यात्रा के अधिकार को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत अन्य देशों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा